

**भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग**

**लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.4183
उत्तर देने की तारीख 26 मार्च, 2025**

तमिलनाडु में 5जी सेवाएं

4183. श्री मलैयारासन डी.:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा तमिलनाडु राज्य में 5जी सेवाएं शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) तमिलनाडु में अब तक 5जी नेटवर्क के अंतर्गत कितने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र शामिल किए गए हैं और राज्य भर में इसे पूरी तरह से शुरू करने की समय-सीमा क्या है;
- (ग) तमिलनाडु में विशेषकर ग्रामीण या दूरदराज के क्षेत्रों में 5जी सेवाओं के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियां क्या हैं और सरकार किस प्रकार से उनका समाधान कर रही है;
- (घ) तमिलनाडु में 5जी अवसंरचना के लिए कुल कितना निवेश किया गया है और राज्य के लिए विशेष रूप से रोजगार, नवाचार और डिजिटल समावेशन के संदर्भ में अपेक्षित आर्थिक लाभ क्या हैं; और
- (ड.) 5जी सेवाओं जैसे हाई-स्पीड इंटरनेट, बेहतर कनेक्टिविटी और तकनीकी प्रगति का लाभ तमिलनाडु के वंचित और आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों सहित समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या पहल की जा रही है?

**उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)**

(क) से (ग) 28 फरवरी 2025 तक दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने तमिलनाडु में 35,655 5जी बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) स्थापित किए हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के सभी जिलों में 5जी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं और तमिलनाडु के 3211 गांवों में 5जी बीटीएस स्थापित किए गए हैं। स्पेक्ट्रम उपलब्धता और मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) मुद्दों सहित 5जी सेवाओं के रोल आउट में आने वाली चुनौतियों का सरकार द्वारा कई पहलों को लागू करके समाधान किया गया है जो निम्नलिखित हैं: -

- i. 5जी मोबाइल सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी।

- ii. समायोजित सकल राजस्व (एजीआर), बैंक गारंटी (बीजी) और ब्याज दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए वित्तीय सुधार।
- iii. वर्ष 2022 और उसके बाद की नीलामी में प्राप्त किए गए स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों को हटाना।
- iv. एसएसीएफए (रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन पर स्थायी सलाहकार समिति) की मंजूरी के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण।
- v. प्रधानमंत्री गतिशक्ति संचार पोर्टल का शुभारंभ और आरओडब्ल्यू अनुमतियों को व्यवस्थित करने और दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना के लिए मंजूरी हेतु आरओडब्ल्यू (मार्गाधिकार) नियमों को लागू करना।
- vi. स्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की स्थापना के लिए स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग हेतु समयबद्ध अनुमति।
- vii. आईआईटी मद्रास में 5जी टेस्ट बेड और तमिलनाडु में उच्च शिक्षण संस्थाओं में सात 5जी यूज केस लैब की स्थापना।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने तमिलनाडु सहित देश भर में 5जी सेवाओं का विस्तार किया है और स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रण नोटिस (एनआईए) में निर्धारित न्यूनतम रोलआउट दायित्वों से अधिक विस्तार किया है। इन दायित्वों से अधिक मोबाइल सेवाओं का विस्तार करना दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के तकनीकी-वाणिज्यिक प्रतिफल पर निर्भर करता है।

(घ) और (ङ) अब तक, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने तमिलनाडु में 5जी सेवाओं के रोल आउट के लिए लगभग 22000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। हाई स्पीड मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता के साथ तमिलनाडु में सेवा से वंचित और आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों सहित समाज के सभी वर्गों में उपयोगकर्ताओं के बीच ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन शिक्षा के साथ-साथ ऑनलाइन सरकारी सेवाओं को अपनाये जाने में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, विभिन्न सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में सात उच्च शैक्षिक संस्थाओं में 5जी यूज केस लैब स्थापित किए गए हैं।
